

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2531
उत्तर देने की तारीख 10 मार्च, 2021

टेली-घनत्व

2531. श्री रवि किशन:

- श्री सुब्रत पाठक:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री बिद्युत बरन महता:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री श्रीरंग आप्पा बरणे:
श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:
श्री संजय सदाशिव राव मांडलिक:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में टेली-घनत्व का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकारी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के बाजार-हिस्से का का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) जिन गांवों में मोबाइल और लैंडलाइन कनेक्टिविटी नहीं है उनकी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा सहित का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार ने ऐसे राज्यों के लिए इस संबंध में किसी योजना पर विचार किया है;
(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा एवं मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और
(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में दूरसंचार सेवा नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु आवंटित, जारी एवं उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) दिनांक 31.01.2021 की स्थिति के अनुसार देश में सेवा क्षेत्र-वार टेली घनत्व का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) दिनांक 31.01.2021 की स्थिति के अनुसार देश में सरकारी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (बीएसएनएल और एमटीएनएल) की बाजार हिस्सेदारी का सेवा क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बसे हुए गांवों की कुल संख्या, मोबाइल कनेक्टिविटी की उपलब्धता वाले बसे हुए गांवों की संख्या और बसे हुए उन गांवों जहां बीएसएनएल लैंडलाइन एक्सचेंज कार्यरत हैं, की संख्या की राज्य-वार सूची अनुबंध-III में दी गई है।

(घ) और (ङ) इस विभाग ने देश के ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित पहल की है:

1. यह विभाग ऑप्टिकल मिक्स ऑफ मीडिया (अर्थात् ओएफसी/रेडियो/सेटेलाइट) से 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक प्रमुख भारतनेट परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। अब तक 154096 ग्राम पंचायतों में उपकरण संस्थापित कर दिए गए हैं और मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान कर दी गई है।

2. वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में चरण-I के तहत मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए 2,343 टॉवर संस्थापित करके परियोजना पूरी हो चुकी है। चरण-II के तहत वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में 4जी मोबाइल सेवाओं के लिए साइटों पर 2,542 टॉवरों की संस्थापना।

3. पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी) के तहत मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए कुल 1,358 टॉवर संस्थापित किए गए हैं जिनमें से 1,355 साइटों से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

4. मोबाइल सेवा से वंचित 85 गांवों में 4जी मोबाइल कवरेज और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एनएच 223 पर निर्बाध 4जी मोबाइल कवरेज का प्रावधान।

5. जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, सीमावर्ती क्षेत्र एवं अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के मोबाइल सेवा से वंचित 354 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी। लगभग 80 गांवों को मोबाइल सेवा से कवर किया जा चुका है।

6. चार राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के महत्वकांक्षी जिलों के मोबाइल सेवा से वंचित 502 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी।

(च) दूरसंचार नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की विभिन्न स्कीमों के तहत संवितरित/आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध-IV एवं V में दिया गया है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 10 मार्च, 2021 को टेली-घनत्व के बारे में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 के भाग (क) के उत्तर से संबंधित अनुबंध

दिनांक 31.01.2021 की स्थिति के अनुसार टेली-घनत्व का सेवा क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र	(प्रतिशत में)
1	आंध्र प्रदेश	98.85
2	असम	69.71
3	बिहार	53.08
4	गुजरात	97.49
5	हरियाणा	93.10
6	हिमाचल प्रदेश	152.14
7	जम्मू और कश्मीर	88.30
8	कर्नाटक	104.19
9	केरल	129.62
10	मध्य प्रदेश	67.40
11	महाराष्ट्र	94.37
12	पूर्वोत्तर	80.51
13	ओडिशा	77.38
14	पंजाब	121.99
15	राजस्थान	83.45
16	तमिलनाडु	106.13
17	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	
18	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	68.76
19	पश्चिम बंगाल	67.21
20	कोलकाता	162.08
21	दिल्ली	275.13
22	मुंबई	148.19
	अखिल भारत	87.00

स्रोत: दूरसंचार विभाग

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 10 मार्च, 2021 को टेली-घनत्व के बारे में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 के भाग (ख) के उत्तर से संबंधित अनुबंध

दिनांक 31.01.2021 की स्थिति के अनुसार सरकारी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (बीएसएनएल एवं एमटीएनएल) की बाजार हिस्सेदारी का सेवा क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र	टेलिफोन कनेक्शनों का शेयर प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	11.46
2	असम	12.56
3	बिहार	7.06
4	गुजरात	9.27
5	हरियाणा	18.81
6	हिमाचल प्रदेश	27.55
7	जम्मू और कश्मीर	11.17
8	कर्नाटक	11.51
9	केरल	26.10
10	मध्य प्रदेश	8.56
11	महाराष्ट्र	8.13
12	पूर्वोत्तर	11.60
13	ओडिशा	19.42
14	पंजाब	15.85
15	राजस्थान	10.05
16	तमिलनाडु	14.36
17	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	11.84
18	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	9.00
19	पश्चिम बंगाल	4.76
20	कोलकाता	10.59
21	दिल्ली	6.19
22	मुंबई	7.26
	कुल	11.15

स्रोत: दूरसंचार विभाग

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 10 मार्च, 2021 को टेली-घनत्व के बारे में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 के भाग (ग) के उत्तर से संबंधित अनुबंध

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बसे हुए गांवों की कुल संख्या, मोबाइल कनेक्टिविटी की उपलब्धता वाले बसे हुए गांवों की संख्या और बसे हुए उन गांवों की संख्या जहां बीएसएनएल लैंडलाइन एक्सचेंज कार्यरत हैं, की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बसे हुए गांवों की कुल संख्या	मोबाइल कनेक्टिविटी की उपलब्धता वाले बसे हुए गांवों की संख्या	बसे हुए उन गांवों की संख्या जहां बीएसएनएल लैंडलाइन एक्सचेंज कार्यरत है
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	396	245	45
2	आंध्र प्रदेश	16158	14371	1289
3	अरुणाचल प्रदेश	5258	3035	41
4	असम	25372	24756	394
5	बिहार	39073	38828	818
6	चंडीगढ़	5	5	10
7	छत्तीसगढ़	19567	17720	298
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	84	84	6
9	दिल्ली	103	103	-
10	गोवा	320	292	79
11	गुजरात	17843	17331	1444
12	हरियाणा	6642	6642	558
13	हिमाचल प्रदेश	17882	17499	529
14	जम्मू और कश्मीर	6101	5947	173
15	झारखंड	29492	28348	289
16	कर्नाटक	27397	26956	1836
17	केरल	1017	1017	1086
18	लद्दाख	236	172	@
19	लक्षद्वीप	6	5	11
20	मध्य प्रदेश	51929	49317	1542
21	महाराष्ट्र	40959	38631	2815
22	मणिपुर	2515	2052	23
23	मेघालय	6459	4785	25
24	मिजोरम	704	498	29
25	नागालैंड	1400	1256	12
26	ओडिशा	47677	41578	680
27	पंजाब	12168	12168	1023
28	पुदुचेरी	90	90	0
29	राजस्थान	43264	42323	1110

30	सिक्किम	425	415	21
31	तमिलनाडु	15049	15000	1145
32	तेलंगाना	10128	9975	609
33	त्रिपुरा	863	832	49
34	उत्तर प्रदेश	97813	97486	1368
35	उत्तराखंड	15745	15319	231
36	पश्चिम बंगाल	37478	37470	820
कुल		597618	572551	20408

@ जम्मू एवं कश्मीर के तहत कवर किए गए हैं।

स्रोत: दूरसंचार विभाग

*स्रोत: बीएसएनएल

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 10 मार्च, 2021 को टेली-घनत्व के बारे में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 के भाग (च) के उत्तर से संबंधित अनुबंध

भारतनेट के अलावा (वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक) पिछले तीन वर्षों में निधि संवितरण

(राशि करोड़ रूपए में)				
क्र.सं.	संचार लेखा नियंत्रकों के नाम	2017-18	2018-19	2019-20
1	अण्डमान और निकोबार	0.03	149.25	297.28
2	आंध्र प्रदेश	33.77	16.48	23.33
3	असम	3.49	6.34	171.81
4	बिहार	65.94	63.07	68.36
5	छत्तीसगढ़	211.46	85.36	90.24
6	दिल्ली	0.04	0.00	0.00
7	दूरसंचार मुख्यालय-बीपीटी 2	0.00	0.00	21.84
8	गुजरात (डी एंड डी और डीएनएच सहित)	14.42	0.00	5.86
9	हरियाणा	6.97	0.95	2.87

10	हिमाचल प्रदेश	5.42	2.70	3.36
11	जम्मू और कश्मीर (लद्दाख सहित)	8.57	0.03	1.26
12	झारखंड	185.56	129.32	149.84
13	कर्नाटक	26.12	0.01	11.41
14	केरल	8.78	0.02	8.39
15	लक्षद्वीप	0.00	39.66	0.00
16	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	64.59	19.34	40.02
17	मध्य प्रदेश	36.99	4.09	9.72
18	पूर्वोत्तर-I (त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम)	1.29	0.08	48.38
19	पूर्वोत्तर-II (नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश)	0.47	0.01	136.52
20	ओडिशा	142.64	72.92	93.82
21	पंजाब	9.89	0.00	3.37
22	राजस्थान	13.04	3.68	4.77
23	तेलंगाना	25.44	19.87	10.30
24	तमिलनाडु	10.32	0.00	6.65
25	उत्तर प्रदेश	78.46	6.75	35.72
26	उत्तराखंड	8.24	0.00	1.21
27	पश्चिम बंगाल	36.78	22.76	21.91
	कुल योग	998.74	642.67	1268.25

स्रोत: दूरसंचार

लोक सभा में दिनांक 10 मार्च, 2021 को टेली-घनत्व के बारे में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 के भाग (च) के उत्तर से संबंधित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतनेट परियोजना के लिए बीएसएनएल द्वारा आवंटित निधि का ब्यौरा

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	राज्य	2017-18	2018-19	2019-20
1	अंडमान और निकोबार	0.16	0.00	12.84
2	असम	12.10	31.91	5.39
3	बिहार	45.23	182.41	308.15
4	छत्तीसगढ़	247.96	269.09	72.15
5	हरियाणा	151.43	59.35	9.95
6	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	3.90	20.80	1.70
7	कर्नाटक	273.83	160.26	35.51
8	केरल	12.51	12.86	6.18
9	महाराष्ट्र	453.49	397.09	91.50
10	मध्य प्रदेश	241.33	136.45	77.21
11	पंजाब	12.77	137.06	319.81
12	राजस्थान	146.62	157.59	110.16
13	उत्तर प्रदेश	147.88	40.37	343.94
14	उत्तराखंड	4.50	67.31	16.34
15	पश्चिम बंगाल	95.86	96.70	25.59
16	सिक्किम	0.20	0.00	0.00
17	पुदुचेरी	0.53	0.82	0.08
18	अरुणाचल प्रदेश	13.97	0.60	3.74
19	मणिपुर	14.63	9.37	3.17
20	मेघालय	19.55	2.08	1.20
21	मिजोरम	12.35	0.78	1.34
22	नागालैंड	16.09	0.18	2.85
23	त्रिपुरा	16.52	9.14	2.48
24	गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	233.31	302.63	996.60

25	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
26	तेलंगाना	113.48	39.42	3.90
27	ओडिशा	46.90	67.92	127.09
28	झारखंड	48.13	122.40	59.81
29	हिमाचल प्रदेश	1.30	4.92	27.48
30	आंध्र प्रदेश	84.80	4.38	159.26
31	तमिलनाडु	110.64	0.00	0.01
कुल		2581.98	2333.86	2825.43
* जीपीओएन और ओएफसी		0.00	127.76	0.00
* बीएसएनएल को तदर्थ भुगतान कर दिया गया है		2302.00	863.00	770.00
टीसीआईएल		0.00	0.00	19.67
बीएसएनएल-बीएसएटी		0.00	0.00	42.38
बैंडविड्थ		0.00	0.00	40.12
कुल योग		4883.98	3324.62	3697.61

स्रोत: दूरसंचार
